जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 280 प्रभात चूरू, शुक्रवार 6 फरवरी, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'इण्डो- यूएस ट्रेड डील पर चार-पांच दिन में दोनों देश संयुक्त बयान देंगे'

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि संयुक्त वक्तव्य के बाद वाइट हाउस के एग्ज़ीक्युटिव आदेश से यूएस टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 05 फरवरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है और दोनों देश चार-पांच दिनों में संयुक्त बयान जारी करेंगे। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा ट्रुथ सोशल पर की गई घोषणा के बाद दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच समझौते की पहली जानकारी सामने आने लगी है।

गोयल ने कहा कि संयुक्त बयान के बाद वाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में 30-45 दिन लगेंगे और इसे मार्च में साइन किया जाएगा।

- पीयूष गोयल ने बताया कि औपचारिक एग्रीमैंट होने में 30 से 45 दिन लगेंगे और संभवतया मार्च तक एग्रीमैंट हो जाएगा और इस पर मार्च में वर्चुअली साइन किये जाएंगे।
- ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा सोमवार रात की थी जिसमें यह भी कहा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। इसे स्पष्ट करते हुए वाणिज्य विभाग के अफसरों ने बताया कि विमान खरीद के ही ऑर्डर 70-80 अरब डॉलर के होंगे। भारत ईंधन, विमान व चिप्स खरीद पर 300 अरब डॉलर खर्च करेगा।
- वेनेज़ुएला से ईंधन खरीदने के ट्रंप के दावे पर विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, वेनेज़ुएला हमारा पुराना सहयोगी है, हम उससे तेल खरीदते रहे हैं। पर प्रवक्ता ने रुस से तेल खरीद के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।

उन्होंने बताया कि संयुक्त समझौते पर वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे और संयुक्त बयान के बाद कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी शुल्क 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

गोयल ने कहा, "हम चाहते हैं कि समझौता जल्दी हो, क्योंकि इसके बाद हमें और रियायतें मिल सकती हैं।"

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, "मार्च में लीगल एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अमेरिका के सामान पर शुल्क कम करेगा।"

ट्रम्प के इस दावे पर भी कुछ स्पष्टता सामने आई कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा।

व्यापार अधिकारियों ने बताया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे थरुर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 फरवरी। संसद के मकर द्वार से व्हीलचेयर से गुजरते हुए, शशि थरूर ने कहा कि वह संसद में अपने कर्तव्यों और केरल में अपने चुनावी कार्य को जारी रखेंगे। ज्ञातव्य है कि बुधवार को थरुर संसद भवन में गिर गए इस कारण उनके पैर में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है।

पत्रकारों से बात करते हुए, तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद थरूर ने कहा कि उनका पैर कास्ट में रहेगा और ठीक होने में कम से कम 4-6 सप्ताह लगेंगे। थरुर ने कहा, "मैं

- कांग्रेस के सांसद शशि थरुर बुधवार को संसद की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गए थे, उनके पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है।

अपना काम जारी रखूंगा, लेकिन मुझे व्हीलचेयर का उपयोग करना होगा, कम से कम इस (बजट) सत्र के इस भाग में शामिल होने के लिए।" बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बुरी नज़र लग गई है, तो थरूर ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "लगे रहने दो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

खड़गे के आवास पर गुरुवार को हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में हुआ बड़ा फैसला

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 फरवरी। गठबंधन राजनीति में शामिल रहने के लगभग डेढ़ दशक के बाद, कांग्रेस ने आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों में अकेले उतरने का फैसला किया है।

1970 के दशक तक प.बंगाल पर कांग्रेस का प्रभुत्व था पर बाद में धीरे-धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती गई और उसकी खाली जगह पर पहले वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। गठबंधन राजनीति से जुड़ने से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं हुआ। वर्ष 2011 में, कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 42 सीटें जीतीं। वर्ष 2016 में, पार्टी ने माकपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और 44 सीटें जीतीं। पिछले 2021 के चुनावों में, कांग्रेस ने फिर से माकपा नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किया, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल सकी।

पार्टी के राज्य नेतृत्व की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित निवास, 10 राजाजी मार्ग पर गुरुवार को हुई बैठक के बाद "एकला चालो" निर्णय लिया गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष

- डेढ़ दशक तक कभी वाम मोर्चा तो कभी तृणमूल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का मन लगता है अब भर चुका है।
- गत चुनाव कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ लड़ा था पर पार्टी का खाता भी नहीं खुला, इसलिए इस बार वाममोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती और तृणमूल पार्टी का रवैया बेहद घमंडी है इसलिए कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
- सत्तर के दशक तक बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था, धीरे-धीरे पार्टी कमज़ोर होती गई तो पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल ने कांग्रेस की छोड़ी हुई जगह हथिया ली।

के नेता राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद थे।

बैठक में राज्य के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को बताया कि वाम मोर्चे के साथ गठबंधन से अब खास सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि वाम नेताओं ने कांग्रेस से "संसाधन तो खींचे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वोट ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं हो सके"। उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ चुनावी समझौते को भी नकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का रुख काफी "घमंडी और अक्खड़" था। पिछले विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर पाई, क्योंकि तृणमूल ने कांग्रेस को "बेहद कम" सीटों का प्रस्ताव दिया था। राज्य के नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का यह मत था कि कांग्रेस सौदेबाजी करने की स्थिति में भी नहीं थी। ममता बनर्जी के भतीजे और वरिष्ठ तृणमूल नेता ने यहां तक कि सुझाव दिया था कि कांग्रेस को तृणमूल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार चुनाव में "कैश ट्रांसफर" के मुद्दे पर आज सुनवाई संभव

चुनाव आचार संहिता के दौरान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रु. देने के खिलाफ प्रशांत किशोर ने याचिका दायर की है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 फरवरी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकार की कल्याण योजना के दुरुपयोग के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वह विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं।

किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मुख्य मुद्दा बिहार सरकार द्वारा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर परिवार की एक महिला को 10,000 रु. सीधे देने का निर्णय लिया था, ताकि वह स्व-रोजगार शुरू कर सके, साथ ही एक और वादा किया गया 2 लाख रु. का, जो

- इस योजना के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दस-दस हजार रु. दिए गए थे और वादा किया गया था कि आकलन के बाद काम संतोषप्रद रहा तो 2 लाख रु. और दिए जाएंगे।
- प्रशांत किशोर ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह योजना विधानसभा की मंजूरी के बिना मंत्रिमंडलीय फैसले के आधार पर लागू कर दी गई थी और इसके लिए सरकार के आकस्मिक कोष से फंड जुटाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन था।
- उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू था तब 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रु. दिए गए थे, यह "भ्रष्ट आचरण" है।

व्यवसाय का आकलन के बाद दिया जाएगा।

याचिका के अनुसार, इस योजना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईसाई रीति से हुए विवाहों का रजिस्ट्रेशन करें- हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्रों को सिविल रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह राज्य का वैधानिक दायित्व है और इसे किसी अधिकारी के विवेकाधीन निर्णय के

- विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपत्तियों को पासपोर्ट, वीज़ा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अधीन नहीं रखा जा सकता। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिरो-मालाबार रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट इंचार्ज फादर पॉल पी की ओर से दायर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावों में बढ़ते "रेवड़ी कल्चर" पर सुप्रीम कोर्ट का रुख गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विषय पर गंभीर चिंतन की जरुरत है इसलिए इस पर तीन सदस्यीय बैंच विचार करेगी

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी घोषणापत्र और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं के वादे करने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक हित से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है और इस पर तीन जजों की बेंच को विचार करना चाहिए।

यह टिप्पणी उस समय की गई जब भाजपा नेता और वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनावी घोषणापत्र और प्रचार के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की है।

यह संकेत देते हुए कि मामला बड़ी बेंच के सामने रखा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बैंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, यह जनहित का गंभीर मुद्दा है और इसे तीन सदस्यीय बैंच द्वारा सुना जाना चाहिए। इसे मार्च में सुना जाएगा तब तक इंतज़ार कीजिए।
- याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों में मुफ्त सामान बांटने के "रेवड़ी कल्चर" पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब सिर्फ सूरज, चांद देने का वायदा किया जाना ही बचा है।
- राजनैतिक दलों ने इस याचिका का विरोध किया तथा इसे राजनैतिक रुप से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं व सब्सिडी शासन का अहम् भाग हैं इसका लक्ष्य कमज़ोर तबकों की मदद करना होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई के दौरान मुद्दे को जटिल बताया था और अपनी न्यायिक सीमाओं की मजबूरी का उल्लेख किया था।

और सार्वजनिक हित का मामला है... इसे तीन जजों की बेंच को सुनना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस महीने के बाद मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा, "मार्च तक इंतजार करें।"

उपाध्याय ने अदालत से मामले की तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगातार वादे कर रहे हैं, जो उनके अनुसार भ्रष्ट आचरण है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संसद में रणनीति पर विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। विपक्ष के संसदीय दल के नेताओं की गुरुवार को संसद भवन परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज्य सभा में

- खड़गे के चैंबर में हुई बैठक में सपा, शिवसेना (उद्धव), आरएसपी, मुस्लिम लीग आदि के नेता शामिल हुए।

दिए गए जवाब तथा अन्य मुद्दों को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई।

बैठक संसद भवन परिसर में राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई जिसमें संसद में सभी दलों ने एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया। बताया जाता है कि इसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इण्डो-यूएस ट्रेड डील पर संयुक्त बयान की प्रतीक्षा में हैं विशेषज्ञ

अभी तक ना तो भारत की तरफ से ही ना ही अमेरिका की तरफ से डील पर कोई स्पष्ट बयान आया है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 फरवरी। भारत और अमेरिका के बीच जिस व्यापार समझौते की काफी चर्चा हो रही है, अब साफ होता जा रहा है कि वह ज्यादा से ज्यादा एक हाई प्रोफाइल दिखावा है। विशेषज्ञ दोनों देशों के संयुक्त बयान का इंतजार कर रहे हैं।

भारत ने अब तक इस समझौते पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, अगर ऐसा कोई समझौता वास्तव में हुआ भी है। अमेरिका ने भी इस समझौते पर कोई विस्तार से बयान जारी नहीं किया है।

अलग अलग संकेतों से पता लगाया जा सकता है कि भारत और अमेरिका, दोनों में इंडो-यू.एस. ट्रेड डील को लेकर क्या हो रहा था। अमेरिका का दबाव भारत पर काम नहीं कर पाया और जब भारत अपनी बात पर अड़ा रहा, तो अमेरिकी पक्ष निराश हो गया। यह बात ट्रम्प के अधिकारियों और खुद डॉनल्ड ट्रम्प की भारत और उसकी आर्थिक संभावनाओं पर की गई टिप्पणियों से साफ नज़र आई।

एक समय डॉनल्ड ट्रम्प ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहा और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। इन घटनाओं से भारतीय टीम और शीर्ष नेतृत्व नाराज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉनल्ड ट्रम्प के फोन कॉल लेने से भी साफ इनकार कर दिया था।

इसी पृष्ठभूमि में भारत और यूरोपीय संघ के बीच अचानक व्यापार समझौता होने और उसके चारों ओर बने कूटनीतिक माहौल ने अमेरिका को अलग-थलग कर दिया। डॉनल्ड ट्रम्प

- हालांकि, ट्रेड डील को लेकर अभी सिर्फ कयास ही लग रहे हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका की दबाव डालने की रणनीति भारत पर कारगर नहीं हुई और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से तो अमेरिका की हताशा और बढ़ गई।
- यही वजह रही कि कभी भारत को "डैड इकॉनमी" बताने वाले ट्रंप ने खुद ही ट्रेड डील स्वीकृत करने की घोषणा कर दी क्योंकि ट्रंप समझ गए कि भारत का विशाल बाजार उनके हाथ से निकल रहा है।
- घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई और डील भी बेहद आकर्षक थी, ऐसे में भारत के इन्कार करने का सवाल नहीं था।
- पर अब देखना यह है कि वास्तव में यह डील क्या रुप लेती है और भारत को कितना लाभ देगी।

को अपने कट्टर दुश्मन, खासकर यूरोप और यूरोपीय संघ के सामने पीछे छूटना पसंद नहीं आया।

ट्रम्प को खोई हुई जमीन को वापस पाने की तत्काल ज़रुरत महसूस हुई और वे मौके की तलाश में थे। उन्होंने वॉशिंगटन से ट्रेड डील की एकतरफा घोषणा कर दी, जिससे भारतीय पक्ष हैरान रह गया।

घोषित व्यापार समझौता भारत के लिए इतना आकर्षक बताया गया कि उसे केवल घोषणा कहकर ठुकराना मुश्किल था। हालांकि भारत ने यह नहीं कहा कि कोई पक्का व्यापार समझौता हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने शिष्टाचार के तौर पर राष्ट्रपति की घोषणा का स्वागत किया।

इस तरह अब केवल अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बड़े दावे ही बाकी रह गए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए जोर-शोर से किया गया दावा है।

ट्रम्प ने भारत से बहुत बड़ी मांग की थी। वह चाहते थे कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ हटा दिए जाएं, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अपने शुल्क बनाए रखे। सही नहीं कहा जा सकता।

भारत की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिकी सामान भारत में बिना शुल्क के आएगा। इसके बजाय कुछ बातों से संकेत मिले हैं कि तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में आने वाले सामान पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क लगाए जाएंगे।

यह संभव नहीं है कि भारत सभी अमेरिकी आयात पर छूट दे, जबकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुवार को ठप्प रही लोकसभा

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। लोकसभा में गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

तीन बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे शुरु होते ही विपक्षी सदस्य फिर से नारेबाजी करने

- लोकसभाध्यक्ष ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करते हुए कहा सदस्य पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा।

लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच कहा कि बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वह लोकसभा के शुरुआत से लेकर आज तक आज तक कभी नहीं हुआ। संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)